

अंबानी के “वनतारा” की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी गठित की

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस चेलमेश्वर के नेतृत्व वाली एसआईटी को 12 सितम्बर तक अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 26 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात स्थित अनंत अंबानी द्वारा स्थापित ‘वनतारा’ रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) का गठन किया है। अदालत ने कहा कि सामान्यतः ऐसे आरोपों पर आधारित याचिका, जिनके समर्थन में कोई ठोस सबूत न हो, कानून की दृष्टि में विचारणीय नहीं होती और प्राथमिक स्तर पर ही खारिज की जानी चाहिए।

इसके बावजूद, कोर्ट ने मामले की तथ्यात्मक जांच पड़ताल के लिए जांच आवश्यक मानी है और एसआईटी को 12 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। एसआईटी का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस जस्ती चेलमेश्वर करेंगे और आयोग के अन्य

- सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश एडवोकेट जया सुकीन व देव शर्मा की याचिका पर दिए जिनमें अखबारों में छपी खबरों के आधार पर पशु अधिकारों के हनन व पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था।

- कोर्ट ने एसआईटी गठित करते समय हालांकि यह भी कहा, कि जिन आरोपों की पुष्टि के लिए ठोस सबूत न हों वे याचिकाएं खारिज कर दी जानी चाहिए पर इस मामले से तथ्यात्मक जांच जरूरी है।

- वनतारा असल में वन्यजीवों का पुनर्वास केंद्र है जहां देश विदेश से जंगली जानवर लाए जाते हैं। इस केंद्र की स्थापना अनन्त अंबानी ने की है।

सदस्य होंगे, बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, राघवेंद्र चौहान, मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त हेमंत नगराले तथा अतिरिक्त आयुक्त, कस्टम्स अनीश गुप्ता। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस पंकज मिथल और पीबी वराले की बैंच ने यह

आदेश एडवोकेट सी.आर. जया सुकीन और देव शर्मा द्वारा दायर दो याचिकाओं के आधार पर पारित किया है। इन याचिकाओं में मांग की गई थी कि वनतारा रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर की कार्यप्रणाली की स्वतंत्र जांच कराई जाए।

याचिकाओं में लगाए गए आरोप अखबारों में छपी रिपोर्टों पर आधारित हैं और उनके समर्थन में कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं किए गए। फिर भी, अदालत ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करने की बजाय, एक तथ्यान्वेषण जांच का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने से जिन मुद्दों पर रिपोर्ट मांगी है, उनमें शामिल हैं: वनतारा द्वारा भारत और विदेशों से जानवरों, विशेष रूप से हाथियों का अधिग्रहण किन परिस्थितियों में और किस प्रक्रिया से किया गया।

क्या ये गतिविधियाँ वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, तथा चिड़ियाघर नियमों के अनुरूप हैं? क्या जानवरों या उनके उत्पादों के व्यापार संबंधी नियमों का पालन किया गया है? क्या वहां पशुपालन, पशु चिकित्सा देखभाल और पशु कल्याण से संबंधित मानकों का पालन हो रहा है?

वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन में 6 की मौत

जम्मू, 26 अगस्त। जम्मू के पास कटरा स्थित श्री माता वैष्णो देवी मार्ग में अर्धकुवारी के पास मंगलवार को भूस्खलन होने से 6 लोगों की मौत हो गयी और 14 अन्य घायल हो गये हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यह जानकारी दी।

श्राइन बोर्ड ने कहा कि अर्धकुवारी के पास हुए इस भूस्खलन में घायल हुए लोगों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। दूसरी ओर जम्मू के सभी स्कूल बुधवार को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। श्राइन बोर्ड और सुरक्षा बलों ने राहत और

- श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी तौर पर रोक दी गई।

बचाव कार्य शुरू कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर माता वैष्णो देवी की यात्रा को अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है। अर्धकुवारी से भवन तक का मार्ग बंद कर दिया गया है। निचले ट्रंक से भी श्रद्धालुओं की आवाजाही सीमित कर दी गई है। जम्मू प्रशासन ने खराब मौसम और क्षेत्र भर में अलग अलग स्थानों पर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने के मद्देनजर सभी सरकारी और निजी स्कूल कल बंद रखने का निर्देश दिया है।

विधानसभा सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक 28 को

जयपुर, 26 अगस्त। सोलहवीं राजस्थान विधान सभा के चतुर्थ सत्र की बैठकें 1 सितम्बर से आरंभ होंगी। इससे पहले विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने, 28 अगस्त को दोपहर 12:30 बजे विधान सभा में अपने कक्ष में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक रफीक खान, बसपा के

- विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने यह परम्परा शुरू की थी।

मनोज कुमार, भारत आदिवासी पार्टी के थावर चन्द और रालोद के डॉ. सुभाष गर्ग को आमंत्रित किया गया है।

देवनानी ने विधान सभा अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद लोकसभा की तर्ज पर विधान सभा में भी सर्वदलीय बैठक बुलाये जाने का निर्णय लिया था। राजस्थान विधान सभा में पहली बार सोलहवीं विधान सभा से आरंभ हुई यह सर्वदलीय बैठक चौथी बार हो रही है।

एससीओ समिट में मोदी और पुतिन का स्वागत खुद करेंगे जिनपिंग

शी इस कदम से ट्रंप को कड़ा मैसेज देना चाहते हैं कि टैरिफ वॉर में “ग्लोबल साउथ” एकजुट है

- चीन में हो रहे तियानजिन समिट में शामिल होने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त को चीन जा रहे हैं। 7 सालों में उनकी यह पहली चीन यात्रा है और भारत और चीन के बीच गंभीर सीमा विवाद को देखते हुए भी यह यात्रा महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

- चीन भी चाहता है कि भारत अमेरिका के पाले में ना जाए क्योंकि एक स्वतंत्र तटस्थ भारत का चीन के साथ आना उसके लिए भी फायदेमंद हो सकता है।

आमंत्रित किया गया है। यह शिखर सम्मेलन भारत और चीन के बीच 2020 को यातक सीमा झड़पों के बाद तनाव कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी हो सकता है, क्योंकि अब भारत पर भी जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

पिछले साल कज़ान, रूस में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी मोदी, शी और पुतिन ने मंच साझा किया था, जबकि उस समय पश्चिमी नेताओं ने यूक्रेन युद्ध के चलते पुतिन से दूरी बना रखी थी। नई दिल्ली में रूसी दूतावास के अधिकारियों ने हाल ही में कहा कि मास्को को शी जिनपिंग और मोदी के साथ त्रिपक्षीय वार्ता की उम्मीद है।

चीनी राष्ट्रपति इस शिखर सम्मेलन

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 26 अगस्त। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा ब्रिक्स देशों और अन्य साझेदारों पर टैरिफ युद्ध थोपने की पृष्ठभूमि में, ग्लोबल साउथ की एकजुटता का संदेश देने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 31 अगस्त से 1 सितंबर तक तियानजिन, चीन में होने जा रहे शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का व्यक्तिगत रूप से स्वागत करेंगे। यह कदम वांशिंगटन को एक सूक्ष्म किंतु स्पष्ट संदेश देने के रूप में देखा जा रहा है।

शी जिनपिंग अगले सप्ताह चीन में एक क्षेत्रीय सुरक्षा मंच पर 20 से अधिक विश्व नेताओं को इकट्ठा करेंगे, जिससे न केवल ट्रंप के समय ग्लोबल साउथ की शक्ति का प्रदर्शन होगा, बल्कि प्रतिबंधों से जुझ रहे रूस को एक और कूटनीतिक जीत पाने में मदद मिलेगी।

पुतिन और मोदी के अलावा, मध्य एशिया, मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के नेताओं को भी

हैल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर से जी.एस.टी. पूर्णतया हटेगी?

3-4 सितम्बर को दिल्ली में आयोजित जी.एस.टी. काउंसिल की बैठक में यह निर्णय पारित होने की सम्भावना

- भारत में इंश्योरेंस का प्रसार न्यूनतम है. अन्य उभरते देशों की तुलना में। इंश्योरेंस प्रिमियम पर 18 प्रतिशत जी.एस.टी. लगती है, यह जी.एस.टी. लगना बन्द हो जाने के बाद मध्यम वर्ग में इंश्योरेंस का प्रचलन बढ़ने की भारी उम्मीद है।

- एक मध्यमवर्ग परिवार को बीस हजार रुपये प्रतिवर्ष की वार्षिक किश्त काफी भारी पड़ती है, और इस किश्त पर 3600 रु. का जी.एस.टी. का भार और पड़ता है।

- अगर जी.एस.टी. इंश्योरेंस पर लगना बंद हो जाये तो मध्यमवर्गीय परिवार पर 3600 रु. का भार कम हो जाता है, और सरकार को आशा है, इससे हैल्थ इंश्योरेंस व लाइफ इंश्योरेंस का “पैनिट्रेशन” बढ़ेगा (प्रसार बढ़ेगा) और बीमारी के इलाज के लिए मध्यम वर्ग को जमीन-जायदाद बेचकर इलाज कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

परिवार बीमा लेने के लिए प्रोत्साहित होंगे। ऐसे देश में, जहाँ जब से मेडिकल खर्च करना अक्सर परिवारों को कर्ज में डुबो देता है, सुरक्षा की लागत को कम करना न केवल आर्थिक रूप से उचित है, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी

आवश्यक है। राश्यों के संघियों के एक समूह ने पहले ही इस प्रस्ताव को समर्थन दे दिया है कि व्यक्तिगत और पारिवारिक स्वास्थ्य तथा टर्म जीवन बीमा योजनाओं (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राजनीतिक दल पूर्व न्यायाधीश सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ टिप्पणी को “तैलुगु सम्मान” को आहत करने का प्रयास बताकर प्रचारित कर रहे हैं

- जाल खंबाता -
- राद्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 26 अगस्त। उपराष्ट्रपति चुनाव ने अप्रत्याशित रूप से सत्तारूढ़ एनडीए के भीतर हलचल पैदा कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बी. सुदर्शन रेड्डी पर की गई तीखी टिप्पणी से तेलुगु राजनीतिक हलकों में बैचैनी बढ गई है। शाह ने फिर दोहराया कि सुदर्शन रेड्डी द्वारा सलवा जुद्धम आंदोलन पर दिए गए ऐतिहासिक निर्णय ने छत्तीसगढ में नक्सलवाद को नई जिंदगी दी।

हालांकि शाह ने यह स्पष्ट किया कि “हिंसा से लडने के लिए एक और हिंसक समूह बनाना केवल दोनों पक्षों के आतंक को बढ़ाता है,” लेकिन यह टिप्पणी अब राष्ट्रीय सुरक्षा से इतर क्षेत्रीय पहचान और गरिमा के नजरिए से देखी जा रही है-खासकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में।

वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक इसे 1980 के दशक में एन.टी. रामाराव की राजनीतिक उदय के समय से जोड़कर देख रहे हैं, जब राजीव गांधी द्वारा तत्कालीन आंध्र मुख्यमंत्री टी. अंजैया के

- इस प्रचार के दबाव में आंध्र व तेलंगाना के सांसद “तेलुगु सम्मान” की रक्षा में खड़े हो सकते हैं।
- सम्भावना बन रही है, कि चन्द्रबाबू नायडू की पार्टी के सांसद, “एन-ब्लॉक” न्यायाधीश सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में वोट करने को मजबूर हो जायें और उपराष्ट्रपति का चुनाव, जिसे सामान्य, साधारण सा चुनाव माना जा रहा था, सरकार के लिए खतरे की घण्टी न बन जाये।
- जैसा, कि विदित ही है, गृहमंत्री अमित शाह ने न्यायाधीश सुदर्शन के खिलाफ टिप्पणी की थी कि, न्यायाधीश के सलवा जुद्धम आन्दोलन के खिलाफ दिये गये निर्णय से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को “नई जिंदगी” मिल गई थी।

अपमान की घटना ने तेलुगु स्वाभिमान की लहर पैदा की थी और उसी भावना को आधार बनाकर ने तेलुगु देशम पार्टी खड़ी की थी। आज, विश्लेषकों का मानना है कि शाह की टिप्पणी-चाहे वह अप्रत्यक्ष हो क्यों न हो-एक सम्मानित तेलुगु न्यायविद् पर हमला मानी जा सकती है, और इसे तेलुगु अस्मिता पर प्रहार माना जा सकता है।

तेलुगु देशम पार्टी, जो एनडीए को एक प्रमुख घटक है, के सांसद जनमत

के दबाव में आकर न्यायमूर्ति रेड्डी का समर्थन करने के लिए मजबूर हो सकते हैं भले ही पार्टी स्तर पर कोई औपचारिक निर्णय न लिया गया हो। अब बहस केवल गठबंधन निष्ठा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तेलुगु नेताओं की प्रतिष्ठा की रक्षा से भी जुड चुकी है। हैदराबाद के एक वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक का कहना है, कि अमित शाह की बातों का असर ऐसा हो सकता (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कौन पैदा करवा रहा है “ट्राइबल लीडर” बिरसा मुंडा और अम्बेडकर के बीच टकराव की स्थिति?

कोटा में भारतीय रेल्वे एस.सी./एस.टी. एसोसिएशन को आवंटित आवास में अम्बेडकर की मूर्ति के समक्ष अनाधिकृत तरीके से क्वाों लगाई गई बिरसा मुंडा की मूर्ति?

- इस मामले में हाईकोर्ट के समक्ष दायर याचिका में कहा गया कि एसोसिएशन के अधिकारी “ट्राइबल” महानायक बिरसा मुंडा द्वारा, अनुसूचित जनजाति के हकों के लिए किए गए संघर्ष का भरपूर सम्मान करते हैं, परन्तु जिस जोर-जबर्दस्ती और अनाधिकृत तरीके से उनकी मूर्ति स्थापित की गई, उससे केवल अनुसूचित जाति की भावनाओं को आहत करने की कोशिश की गई है।
- याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 2022 में एसोसिएशन का चुनाव हार चुके एक गुट ने लोकसभा अध्यक्ष, ओम बिड़ला, के ओ.एस.डी. के साथ मिलकर अनाधिकृत तरीके से मूर्ति लगाने का कृत्य किया।
- याचिकाकर्ताओं का कहना है कि एफ.आई.आर. भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन, राजनैतिक दबाव के चलते एफ.आर. लगाकर मामले को ठण्डे बस्ते में डाल दिया गया।

ईकाई ने हाईकोर्ट में रिट याचिका इसलिए दायर की थी क्योंकि पिछले वर्ष लोकसभा अध्यक्ष, ओम बिड़ला, के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (ओ.एस.डी.) ने एसोसिएशन को आवंटित

भवन में जबरदस्ती घूसकर, डॉ. भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति के सामने ही अनाधिकृत, अवैध तरीके से झारखण्ड प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के महानायक, बिरसा मुंडा, की मूर्ति का

लोकार्पण किया, और अनुसूचित जाति के सदस्यों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई।

याचिकाकर्ता के वकील सतीश पचौरी का कहना है कि वे बिरसा मुंडा के अनुसूचित

जनजातियों के अधिकारों के लिए किए गए संघर्ष और योगदान का सम्मान करते हैं, परन्तु एसोसिएशन को आवंटित परिसर में उनकी मूर्ति स्थापित करने का कोई सरकारी आदेश नहीं था और केवल बलपूर्वक अनुसूचित जाति के सदस्यों की गरिमा को आहत करने के लिए यह कृत्य किया गया है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि 2022 में एसोसिएशन के चुनाव में एक गुट चुनाव हार गया था, जिसने प्रतिशोध लेने के लिए एसोसिएशन को आवंटित इस आवास की शांति भंग करने की कोशिश की है। इस मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया था कि मूर्ति स्थापित करने से पूर्व राजीव दत्ता व उनके सहयोगियों ने कोई तरीके की स्वीकृति प्राप्त नहीं

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- नोटिस के अनुसार 27 अगस्त को रात 12.01 के बाद भारत के गोदामों से निकले माल पर यह टैरिफ लगेगा।

समय में उठाया जा रहा है, जब रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते की कोशिशें ठप पड़ती नजर आ रही है। नोटिस में साफ कहा गया है कि यह बढ़ा हुआ टैरिफ भारत के उन उत्पादों पर लागू होगा, जो 27 अगस्त, 2025 को सुबह 12:01 बजे (पूर्वी डेलाइट समय) के बाद खपत के लिए आयात (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जालोर जैसे शुष्क जिले में भी आठ जने नदी में डूबे

जालोर जिले में इस वर्ष हो रही मूलसलाधार बारिश के कारण कई नदी नाले उफान पर हैं, जिले की सुकड़ी नदी में दो अलग-अलग जगह पर हादसे हुए

जालोर, (कासं)। जालोर जिले में मानसून की सक्रियता के चलते मंगलवार शाम को भी मूसलाधार बारिश का दौर जारी रहा। वहीं जालोर जैसे शुष्क जिले में आठ जने नदी में बह गये, जिनकी मौत हो गई। जालोर की जीवन रेखा कही जाने वाली जवाई नदी में पानी की आवक तेज देखी गई। आसाना गांव में सुकड़ी नदी में डूबने से छह लोगों के मरने की सूचना है। इसके अलावा सांथू गांव के दो जनों की सुकड़ी नदी में बहने से मौत हो गई। बारिश के चलते कई जगह नदी-नाले उफान पर होने से मार्ग अवरुद्ध रहे।

जालोर में लगातार बारिश से जिलेभर में नदी नालों में पानी की आवक तेज देखी गई। जवाई नदी के निकट आने वाले क्षेत्र के नालों में पानी आने से मार्ग अवरुद्ध हो गए। सायला के निकट आसाना गांव में मंगलवार शाम को सुकड़ी नदी में बहने से छह लोगों की मौत होने की सूचना मिली। शाम को सुकड़ी नदी में आसाना गांव के छह युवक बोलेरो गाड़ी लेकर नदी किनारे नहाने गये थे। उस दौरान पानी के तेज बहाव के साथ छह युवक बह गये। ग्रामीणों के अनुसार थलवाड़ रोड पर नदी के दूसरे किनारे पर बोलेरो गाड़ी छोड़कर नदी की रफ्त पर स्नान करते हुए दूसरे किनारे आए थे। रफ्त से वापस दूसरी तरफ जाते समय पानी के वेग में संतुलन बिगड़ने से एक युवक के बहने पर बचाने के चक्कर पर सभी साथ में बह गए। नदी किनारे खड़े दूसरे लोगों ने देखकर ग्रामीणों को सूचना दी, जिस पर सायला एसडीएम सुरजभान विश्नोई, तहसीलदार लक्ष्मी चौधरी,



बीमार बुजुर्ग को सिविल डिफेंस की टीम व समाजसेवी लोगों ने नाव की सहायता से इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया।

- पानी के वेग में संतुलन बिगड़ने से एक युवक के बहने पर बचाने के चक्कर पर सभी साथ में बहे
- आसाना गांव में सुकड़ी नदी में डूबने से छह लोगों की मौत, वहीं सांथू गांव के दो जनों की सुकड़ी नदी में बहने से मौत हो गई
- जालोर शहर का सुन्देलाव तालाब ओवरफ्लो होने से गंदा पानी कॉलोनिyों में जाने से जलमग्न हो गई
- बीमार बुजुर्ग को भी सिविल डिफेंस की टीम व समाजसेवी लोगों ने खाट पर उठाकर तथा बाद में नाव की सहायता से अस्पताल पहुंचाया

थानाधिकारी सुरेंद्रसिंह मौके पर पहुंचे तथा युवकों की खोजबीन के लिए एसडीआरएफ की टीम भीनमाल को मौके पर बुलाया। देर शाम तक बचाव दल को नदी में तेज बहाव के चलते उन्हें ढूँढने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

वहीं सुकड़ी नदी का मिलन जवाई नदी से तुरा गांव के पास होगा। ऐसे में एक तरफ सुकड़ी नदी व दूसरी तरफ जवाई नदी का पानी तेज गति से बहने से कई गांवों के रास्तों का सम्पर्क टूट गया है। वहीं सांथू गांव में भी सुकड़ी नदी में बहने से पसिया देवी व छोटाराम की मौत हो गई। इस प्रकार सुकड़ी नदी में डूबने से अब तक आठ लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है।

जालोर में मंगलवार शाम को तेज बारिश के चलते सुन्देलाव तालाब भी ओवरफ्लो होने से निचली कॉलोनियों में तालाब का गंदा जाने से कॉलोनियां जलमग्न हो गई हैं। कॉलोनियां में रहने

वाले लोगों के घरों में पानी घुसने से लोगों के लिए परेशानी हो गई है। मंगलवार को एक बीमार बुजुर्ग को भी सिविल डिफेंस की टीम व समाजसेवी लोगों ने खाट पर उठाकर तथा बाद में एक नाव की सहायता से इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। कॉलोनी के चारों तरह पानी भर जाने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जालोर में तेज बारिश के चलते सुकड़ी, जवाई, आकोली नदी पूरे उफान पर बह रही है। वणधर, बांडी, सिणधरा व बांकली बांध में भी पानी की आवक तेज गति से हो रही है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जवाई में भी पचास फीट से अधिक पानी की आवक हो गई है। जालोर में मूसलधार बारिश का दौर जारी रहने से जगह जगह पानी भर गया। बस स्टैण्ड, शिवाजी नगर सहित कई कॉलोनियों में पानी भर जाने से आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

कार सहित नदी में डूबे तीन युवकों की मौत

उदयपुर, (कासं)। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा थाना क्षेत्र लकोड़ा पावर हाउस के समीप बायडी पुलिया में डूबी कार में सवार तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि दो जनों को बाहर निकालकर उनकी जान बचा ली गई। सोमवार रात में खेरवाड़ा से बावलवाड़ा रोड़ पर लकोड़ा पावर हाउस के आगे बायडी पुलिया विकट मोड़ पर कार अनियंत्रित होने पर पानी में बह गई। हादसे में कार में सवार लकोड़ा निवासी ध्रुव पुत्र कैलाश चन्द्र पटेल, लव पुत्र कांतिलाल पटेल निवासी बायडी, मउडीया बावलवाड़ा निवासी नरेश उर्फ पिंटु पुत्र नाना पोखरिया की मौत हो गई तथा प्रवीण पुत्र भराजी व लक्ष्मण पुत्र देवीलाल निवासी बावलवाड़ा की कार से बाहर निकलने से जान बच गई। चालक लव खेरवाड़ा में बैकरी चलाता था एवं कार लेकर ध्रुव दोनों गांव लौट रहे थे। इस दौरान नरेश, प्रवीण व लक्ष्मण तीनों अहमदाबाद से मजदूरी कर खेरवाड़ा आए, जिन्होंने गांव जाने के लिए एलिफ्ट मांगी। इस पर लव उन्हें गांव ले जाने के लिए कार में बैठा कर खाना हुआ, जहां बीच रास्ते हादसा हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने उदयपुर से एनडीएआरएफ की टीम को बुलाया। टीम ने मशक्कत कर ध्रुव व नरेश के शव को बाहर निकला खेरवाड़ा मोर्चों में रखवाया।

ट्रक और बाइक की टक्कर में दो की मौत, एक घायल

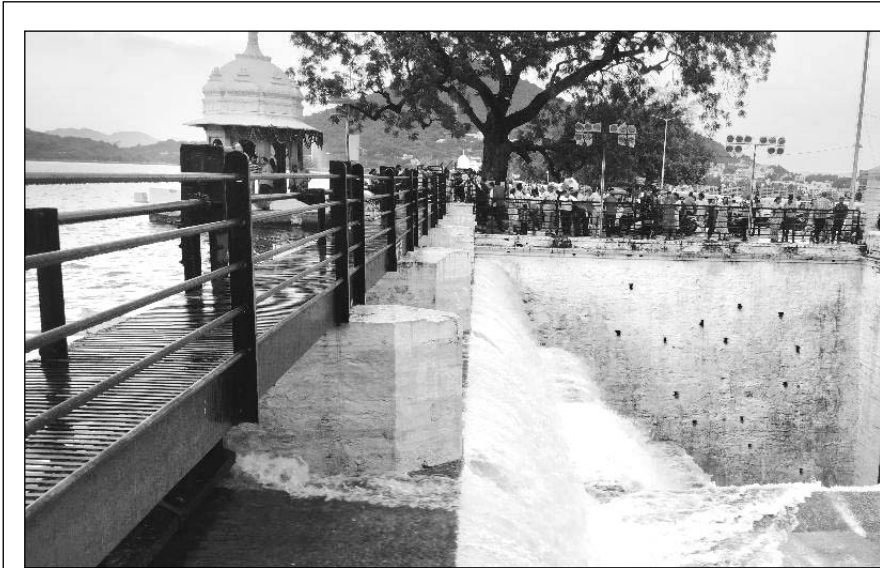
भीलवाड़ा, (निसं)। जिले की आसीद विधानसभा क्षेत्र के शंभूगढ़ थाना इलाके में खेजड़ी चौराहे पर दर्दनाक सड़क हादसे में एक जने की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं एक अन्य घायल का उपचार जारी है।

हादसा एक तेज रफ्तार ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर से हुआ। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने खेजड़ी चौराहे पर एनएच-148डी को जाम कर दिया, जिससे यातायात बाधित हो गया। बताया जा रहा है कि यह हादसा सुबह करीब दस बजे हुआ, जब एक ट्रक ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल सवार एक अज्ञात युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान एक और युवक ने दम तोड़ दिया। हादसे के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण और महिलाएं मौके पर जमा हो गए। उन्होंने हाइवे पर बढ़ते हादसों को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया और हाईवे 148डी

- आक्रोशित ग्रामीणों ने खेजड़ी चौराहे पर एनएच-148डी को जाम कर दिया, जिससे यातायात बाधित हो गया

को जाम कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि खेजड़ी चौराहे पर आए दिन हादसे होते रहते हैं और पिछले तीन महीनों में दर्जनों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ग्रामीणों की मुख्य मांग है कि इस चौराहे पर वाहनों की रफ्तार को नियंत्रित करने और हादसों को रोकने के लिए एक पुल (फ्लाईओवर) बनाया जाए। उनका कहना है कि सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं होने के कारण, यहां के खतरनाक मोड़ और चौराहे पर तेज रफ्तार गाड़ियां आए दिन दुर्घटनाग्रस्त होती हैं। हंगामे की सूचना मिलते ही शंभूगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से सम्झौते का प्रयास किया। पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है, जिसके बाद ही जाम खुलवाया जा सका।

फर्जी टीटी को पकड़ा :- कोटा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के टिकट चैक करते हुए एक व्यक्ति को रेलवे पुलिस ने पकड़ा और जीआरपी पुलिस को सौंप दिया। संदिग्ध व्यक्ति सवाईमाधोपुर का रहने वाला है जो अवध एक्सप्रेस से सवाईमाधोपुर से कोटा आया था और खुद को टीटीई बताकर कोटा के प्लेटफार्म नम्बर एक पर पार्सल कार्यालय के समीप रेल यात्रियों की टिकट चैक कर रहा था, इस दौरान मामले में सामने आया कि व्यक्ति ने फर्जी टीटीई बनकर प्लेटफार्म पर घूम रहे अवैध बेंडरों को भी पकड़ा और उनकी रसीद भी काटी। प्लेटफार्म पर घूम रहे रेलवे पुलिस के जवान को टिकट चैकिंग कर रहे व्यक्ति पर संदेह हुआ तो फर्जी टीटी से पूछताछ की तो वह घबरा गया। रेलवे पुलिस ने व्यक्ति को जीआरपी पुलिस को सौंप दिया।



उदयपुर शहर की विश्व प्रसिद्ध फतहसागर झील लबालब होकर ओवरफ्लो हो गई। मंगलवार शाम 4.30 बजे इसके चारों गेट तीन-तीन इंच खोले गए। गणेश चतुर्थी की पूर्व संध्या पर मंगलवार को उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा, संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी, जिला कलेक्टर नमित मेहता, युडीए आयुक्त राहुल जैन, समाजसेवी गजपालसिंह आदि ने हजारों शहरवासियों की उपस्थिति में पूजा-अर्चना कर फतहसागर के गेट खोले। इसके साथ ही समूचा उदयपुर खुशी से झूम उठा। पाल पर मौजूद लोगों ने जयकारे लगाकर खुशी व्यक्त की। उदयपुर में गत दिनों हुई लगातार बारिश से झीलों में तेजी से पानी की आवक हो रही है।

रायला में सरकारी विद्यालय का कक्षा-कक्ष ढहा, बड़ा हादसा टला

कार्यालय नगरपालिका महवा (दौसा) राज0
EMAIL:-nagarpalikamahawa@gmail.com फोन नं.- 07461 284005

क्रमांक-नयाप / 2025-26 / 401 दिनांक- 22.08.2025

-: निविदा आमंत्रण सूचना :-

नगर पालिका महवा द्वारा विभिन्न कार्यों की निविदा आमंत्रित की गई है जिसकी निविदा सूचीए नं. (DLB2526SLRC15522, DLB2526SSRC15523) है। निविदा सूचना एवं शर्तें राजस्थान उपपान पोर्टल की वेबसाइट www.sppp.raajasthan.gov.in एवं www.eproc.raajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।
राज.संवाद/सी/25/8793 अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका महवा

कार्यालय जिला परिषद (पंचायत प्रकोष्ठ) करौली

क्रमांक :- वि/सक/निविदा/2025-26/281 दिनांक :- 21/08/2025

ई-निविदा सूचना 01/2025-26

जिला परिषद करौली के अधीन पंचायत समिति श्री महावीर जी मे स्वीकृत पंचायत समिति भवन निर्माण कार्य का पंचायतीराज अधिनियम 1996 के नियम 181 के अन्तर्गत आमंत्रित ई-निविदा (अनुमानित राशि 208.70 लाख) की विस्तृत जानकारी हेतु ऑन-लाईन वेब-साइट <http://sppp.raajasthan.gov.in> & <http://eproc.raajasthan.gov.in> पर देखी व डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है तथा कार्यालय समय में कार्यालय में देखी जा सकती है।
UBN :- ZKR2526WSOB00406
NIB Code :- ZKR2526GA0303 मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राज.संवाद/सी/25/8775 जिला परिषद करौली

Office of the Medical Superintendent
RUHS Hospital of Medical Sciences, Jaipur
Sector-11, Kumbha Marg, Pratap Nagar, Tonk Road, Jaipur - 302033(Raj.)
☎99898 0141-2795577, Email: sppp.hms@ruhsraj.org, ruhsms@ruhsraj.org

No. :- F () RUHS HMS/Store/2025-26/8569 Date :- 25/08/2025

Notice Inviting e-Bids

Single Stage Two envelope Online bids (e-bids) are invited upto 02.00 pm of 26/09/2025 for Supply and Installation of 1. High End Surgical Microscope for Plastic and Reconstructive Surgery, Qty. 01, Total Approx. Cost Rs. 2,50,00,000.00, 2. Electric Saw and Drill System with Attachments, Qty. 01, Approx. Cost Rs. 40,00,000.00 at Dept. of Plastic Surgery, RUHS Hospital of Medical Sciences, Jaipur. Details may be seen in the Bidding Documents at the Website sppp.raaj.nic.in or eproc.raajasthan.gov.in.
UBN :- CMS2526GLOB0000788
Raj.Samwad/C/25/8741 Medical Superintendent

कार्यालय उप वन संरक्षक (वन्यजीव) राष्ट्रीय चम्बल घाटियाल अभ्यारण्य, धौलपुर
महिला पुलिस थाने के पास हाउसिंग बोर्ड पुरानी छावनी, धौलपुर पिन कोड 328001
email id : dcfwl.ncs.forest@gmail.com

क्रमांक :- एक () / उदरसं/वन्यजीव / रायचण / 2025-26/2222 दिनांक:-18/8/25

Notice Inviting Bid

Bid for providing Construction of Choki with solar Pump at Forest Block of Wildlife Range Samthura of DCF WL NCS Dholpur are invited from interested bidders upto 11.30 AM, 29.8.2025 other particulars of bid may be visited on the procurement portal <http://sppp.raajasthan.gov.in>, <http://eproc.raajasthan.gov.in> of the state The approximate value of the Procurement is 40.00 lakhs. UBN No. FOR2526WSB01380

(डॉ. आशीष व्यास)

DIPR/C/12141/2025 उप वन संरक्षक (वन्यजीव) राष्ट्रीय चम्बल घाटियाल अभ्यारण्य धौलपुर

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले की शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के रायला कस्बे की जनता कॉलोनी स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय का एक कक्षा-कक्ष मंगलवार सुबह अचानक तेज धमाके के साथ जमींदोज हो गया। स्कूल परिसर में उस समय 73 बच्चे मौजूद थे, लेकिन गनीमत रही कि जिस कक्ष का मलबा गिरा, उसे पहले ही अधिकारियों ने सील कर दिया था। यही सर्कतता मासूम बच्चों के लिए जीवनदायी साबित हुई और एक बड़ा हादसा टल गया। ग्रामीणों और स्कूल स्टाफ के अनुसार विद्यालय का यह भवन लंबे समय से जर्जर हालत में था। भवन की दीवारों में दरारें आ चुकी थीं और छत भी कमजोर हो गई थी।

प्रधानाध्यापक एहसान अली ने बताया कि विद्यालय के पीछे पानी भरने की समस्या लंबे समय से बनी हुई है, जिससे नींव कमजोर हो गई थी। इस बार में उच्च अधिकारियों को कई बार अवगत कराया गया। बनेड़ा उपखंड अधिकारी श्रीकांत व्यास व शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कुछ दिन पहले विद्यालय का निरीक्षण किया था। निरीक्षण में भवन की स्थिति को बेहद खतरनाक पाया गया था। इसी आधार पर संबंधित कक्ष को सील कर सील कर दिया गया और बच्चों की पढ़ाई खुले मैदान में शुरू करवा दी गई। मंगलवार सुबह करीब 8.40 बजे जब विद्यालय में प्राधाना खतम हो गई थी कि अचानक एक जर्जर कक्षा कक्ष जोरदार धमाके के साथ गिर पड़ा। आवाज सुनकर बच्चे सहम गए और आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में ग्रामीण और अभिभावक विद्यालय परिसर में जमा हो गए। राहत की बात



शाहपुरा क्षेत्र के रायला कस्बे में राजकीय प्राथमिक विद्यालय का एक कक्षा-कक्ष जमींदोज हो गया।

- हादसे के दौरान स्कूल परिसर में 73 बच्चे मौजूद थे, गनीमत रही कि जिस कक्ष का मलबा गिरा, उसे पूर्व में अधिकारियों ने सील कर दिया था
- ग्रामीणों और स्कूल स्टाफ के अनुसार विद्यालय का यह भवन लंबे समय से जर्जर हालत में था

यह रही कि सील किया गया कमरा खाली था और उस ओर किसी का आना-जाना नहीं होता था। घटना के समय विद्यालय में 73 बच्चे मौजूद थे, जबकि स्कूल में 98 बच्चों का नामांकन है। हादसे की खबर सुनते ही बच्चों के अभिभावक भी तुरंत स्कूल पहुंचे। ग्रामीणों ने कहा कि यदि यह कमरा सील नहीं किया गया होता, तो आज कोई बड़ा हादसा सामने आ सकता था। बच्चों को सुरक्षित देखकर सभी ने राहत की सांस ली। हालत यह है कि 98 बच्चों का नामांकन होने

के बावजूद स्कूल का संचालन मात्र दो कमरों के किया जा रहा था, जिसे भी जर्जर होने के कारण 28 जुलाई को सील कर दिया गया, जिसके कारण बरसात के बीच भी बच्चे खुले मैदान में पढ़े के नीचे एक साथ पढ़ने को मजबूर थे। ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय भवन के जर्जर होने की शिकायतें काफी समय से की जा रही थीं, लेकिन हर बार मामला अनदेखा होता रहा। समय रहते कदम नहीं उठाए जाते तो मंगलवार को मासूमों की जान पर भारी खतरा मंडरा

सकता था। ग्रामीणों ने प्रशासन से इस पूरे मामले में गंभीरता दिखाने और भविष्य में ऐसी लापरवाही नहीं दोहराने की अपील की। स्कूल भवन का कमरा गिरने के बाद ग्रामीणों और अभिभावकों ने जोर देकर कहा कि बच्चों को खुले मैदान में पढ़ाना लंबे समय तक संभव नहीं है। गर्मी और बरसात के मौसम में यह स्थिति और भी कठिन हो जाएगी। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द विद्यालय भवन का पुर्ननिर्माण किया जाए ताकि बच्चों को सुरक्षित वातावरण मिल सके। शिक्षा विभाग की ओर से बताया गया कि गिरे हुए कमरे का मलबा जल्द ही हटवाया जाएगा और भवन के पुर्ननिर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विभाग का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है और उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे।

छात्रा ने आत्महत्या की

डूंगरपुर, (निसं)। दोवडा थाना क्षेत्र के पाल मांडव गांव में 11वीं कक्षा की एक छात्रा ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के वक्त छात्रा घर में अकेली थी। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। दोवडा थाने के एसआई ने बताया कि पाल मांडव गांव निवासी अभिलाषा परमार 11 वीं कक्षा की छात्रा थी और दामडी गांव के परकारी स्कूल में पढ़ती थी। अभिलाषा के पिता दिनेश परमार मुंबई में मजदूरी करते हैं। आज अभिलाषा की मां शारदा गांव में सामान

लेने बाजार गई थी। अभिलाषा घर पर अकेली थी। शारदा देवी जब सामान लेकर वापस घर लौटी तो देखा कि अभिलाषा घर में फंदे पर लटक ली हुई थी। शारदा ने चिल्लाकर परिजनों और पड़ोसियों को बुलाया। परिजनों ने अभिलाषा को फंदे से नीचे उतरा और जिला अस्पताल लेकर आए जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पोस्टमॉर्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। परिजनों ने एक युवक पर अभिलाषा को पेशान करने का आरोप लगाया है।

Govt. Of Rajasthan
Office of the Executive engineer
Watershed development and soil conservation, Jalore
No-Jalore/E-tender/2025-26/Jalore/MJSA 2.1/237 Date:-19.08.2025

NOTICE INVITING BID / NIT No- 04/2025-26

Bids for package of construction of tanka with agor and RTWHS (33 works) MJSA 2.1 Block Jalore in jalore district of estimated value total 4222960 Rs are invited from interested bidders on date 28.08.2025. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (<https://eproc.raajasthan.gov.in> or <https://sppp.raajasthan.gov.in>) of the state. UBN No:- WSC2526WSOB01133 / NIB No:- WSC2526A0654

Narendra Sharma
Executive Engineer, Watershed Development & Soil Conservation Jalore
DIPRC/12262/2025

कार्यालय नगरपालिका रामगंजमण्डी जिला-कोटा (राज0)

क्रमांक :- न.पा.रा. / 2025 / 755 दिनांक :- 22.08.2025

ई-निविदा सूचना 11 / 2025-26

नगरपालिका रामगंजमण्डी द्वारा कार्यों हेतु पालिका में पंजीकृत एवं विभागों में AA-A.B, Class एवं उपयुक्त श्रेणी संवेदको से लिफाफा पद्धति / ई-निविदा पद्धति से ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्य की निविदा बेचे जाने की दिनांक 25.08.2025 से 11.09.2025 एवं अपलोड करने की दिनांक 25.08.2025 से 11.09.2025 सांय 6 बजे तक। ई.एम.सी. / निविदा शुल्क / प्रोसेसिंग फीस प्राप्त करने की तिथि :- 12.09.2025 समय प्रातः 11.00 बजे तक। तकनीकी बिड खोलने कि दिनांक 12.09.2025 को दोप. 2.00 बजे बाद रहेगी। वित्तीय बिड तकनीकी परीक्षण उपरांत खोली जावेगी। निविदा शर्तें आदि सम्पूर्ण विवरण <http://sppp.raaj.nic.in>, <http://eproc.raajasthan.gov.in> देखी जा सकती है।

SR.NO	NIB	UBN
1	DLB2526A5003	DLB2526WSOB15475

राज.संवाद / सी / 25 / 8778 अधिशाषी अधिकारी

अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि. जिला खंड, अजमेर

क्रमांक :- 1536 निविदा सूचना संख्या 12 / 2025-26 दिनांक :- 14.8.2025

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से राज्य निर्माण /सहकृ निर्माण कार्यों हेतु उद्भुतक श्रेणी में वास्तविक निर्माण विभाग राजस्थान के पंजीकृत संवेदको एवं केडीपी /राज्य सरकार व उनके अधिकृत संगठनों /केडीपी सौद निर्माण विभाग/राज्य एवं तुर संभर विभाग/राज्य एवं इण्डिया के निर्माण कार्यों के निविदा प्रपत्र के निविदा प्रपत्र में कुल 07 पैकेज /कार्य/ बिडकी कुल लागत राशि करुबे 3468.01 लाख है, कि एच ई-टेंडरिंग प्रक्रिया हेतु ऑन लाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

निविदा पत्रों डाउनलोड एवं अपलोड करने की तारीख एवं समय	दिनांक 19.8.2025 प्रात 9.30 बजे से 29.8.2025 को सांय 6.00 बजे तक
---	--

निविदा से संबंधित सम्पन्न विवरण वेबसाईट www.dipronline.org पर एवं निविदा प्रकाशने का विवरण वेबसाईट <https://eproc.raajasthan.gov.in> एवं sppp.raaj.nic.in पर देखा जा सकता है। सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया <https://eproc.raajasthan.gov.in> पर ऑनलैन्ड सम्पादित की जावेगी।

UBN No.

1	PWD2526WSRC09788	2	PWD2526WSRC09790	3	PWD2526WSRC09793
4	PWD2526WSRC09797	5	PWD2526WSRC09800	6	PWD2526WSRC09802
7	PWD2526WSRC09803				

DIPR/C/12010/2025

हजारी सल्ल अग्रवाल
अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि.जिला खण्ड, अजमेर

कार्यालय नगरपालिका बिजयनगर जिला-ब्यावर (राज0)

निविदा सूचना 02 वर्ष 2025-26

नगरपालिका बिजयनगर द्वारा पंजीकृत संवेदको से निर्धारित प्रपत्र में E-Procurement प्रक्रिया से www.eproc.raajasthan.gov.in पर ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। संवेदक द्वारा निविदा प्रपत्र, निविदा शर्तों व अन्य विस्तृत जानकारी इंटरनेट वेब साईट www.sppp.raaj.gov.in और www.eproc.raajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

कुल निविदा के कार्य	: 01 कार्य
निविदा की कुल लागत	: रु 49.96 /- लाख
कुल घरोहर राशि	: अनुमानित लागत की दो प्रतिशत
ऑन लाईन निविदा फार्म प्राप्त करने व जमा करवाने की दिनांक	: 25 / 08 / 2025 प्रातः 11.00 बजे से 07 / 09 / 2025 प्रातः 6.00 बजे तक
निविदा शुल्क की.डी., घरोहर राशि डी.ई एवं प्रोसेसिंग शुल्क डी.डी. मौखिक रूप से जमा कराने की अंतिम दिनांक	: 08 / 09 / 2025 प्रातः 11.00 बजे तक
ऑन लाईन निविदा खोलने की दिनांक	: 09 / 09 / 2025 सांय 1:00 बजे

उत्तम निविदा का NIB Code :- DLB2526A5007

नोट :- निविदा दाता द्वारा निविदा शुल्क एवं घरोहर राशि अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका बिजयनगर के नाम से एवं प्रोसेसिंग शुल्क Managing Director, RISL payable at Jaipur के नाम से एवं डिपेंडेंसी ड्राफ्ट (D.D) निविदा जारी होने कि दिनांक के बाद के दिने वाहिए।

अध्यक्ष
नगरपालिका बिजयनगर
राज.संवाद / सी / 25 / 8780

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका बिजयनगर

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किसान हितों के प्रति संवेदनशील प्रदेश में मांग अनुसार उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति एवं अतिरिक्त आपूर्ति की कार्यवाही जारी

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर । राज्य सरकार और कृषि विभाग द्वारा किसानों को उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। विशेष रूप से यूरिया और डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा उर्वरकों की दैनिक उपलब्धता पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। कम उपलब्धता और अधिक खपत वाले जिलों व ब्लॉकों को चिन्हित कर प्रदेश भर में प्राथमिकता के साथ पूर्ण पारदर्शिता से डीएपी व यूरिया का वितरण किया जा रहा है। उर्वरकों की कालाबाजारी व जमाखोरी को रोकने के लिए कृषि विभाग के अधिकारी प्रदेश भर में पूर्ण सतर्कता से कार्य कर रहे हैं।

राज्य सरकार द्वारा निरंतर केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर

प्रदेश की मांग अनुसार उर्वरकों की आपूर्ति करवाई जा रही है। राज्य के किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु खरीफ 2025 में अप्रैल से अगस्त तक भारत सरकार द्वारा आवंटित 8 लाख 82 हजार मैट्रिक टन यूरिया के विरुद्ध अब तक 8 लाख 23 हजार मैट्रिक टन की आपूर्ति की जा चुकी है। अगस्त माह की शेष अवधि में 59 हजार मैट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति राज्य सरकार द्वारा कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

माह अप्रैल से अगस्त तक भारत सरकार द्वारा आवंटित 4 लाख 75 हजार मैट्रिक टन डीएपी के विरुद्ध अब तक 3 लाख 59 मैट्रिक टन डीएपी की आपूर्ति की जा चुकी है, शेष 27 हजार मैट्रिक टन डीएपी की आपूर्ति प्रस्तावित है।

प्रदेश में वर्तमान में 1 लाख 86 हजार मैट्रिक टन यूरिया, 1 लाख 20 हजार मैट्रिक टन डीएपी, 0.81 लाख

■ **खरीफ 2025 में अप्रैल से अगस्त तक भारत सरकार द्वारा आवंटित 8 लाख 82 हजार मैट्रिक टन यूरिया के विरुद्ध अब तक 8 लाख 23 हजार मैट्रिक टन की आपूर्ति की जा चुकी है।**

■ **अगस्त माह की शेष अवधि में 59 हजार मैट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति राज्य सरकार द्वारा कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।**

मैट्रिक टन एनपीके एवं 1 लाख 93

हजार मैट्रिक टन एसएसपी उर्वरकों का स्टॉक उपलब्ध है। वर्तमान में गत वर्ष की तुलना में फॉस्फेटिक उर्वरकों का स्टॉक 1 लाख मैट्रिक टन अधिक है एवं आपूर्ति जारी है। यूरिया की लगभग 8000 मैट्रिक व डीएपी की 10 हजार 900 मैट्रिक उर्वरक रेल द्वारा परिवहन में है।

केंद्र सरकार की ओर से यूरिया, डीएपी एवं अन्य उर्वरकों का राज्यों को माहवार व कंपनीवार आवंटन किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा प्राप्त आवंटन एवं जिलों की मांग के अनुसार जिलेवार आपूर्ति योजना तैयार कर प्रदेश में उर्वरकों को वितरण कराया जाता है।

राज्य सरकार किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध हो कर कार्य कर रही है और यह सुनिश्चित करने हेतु हर संभव प्रयास कर रही है कि खेती-किसानी में किसी प्रकार की बाधा न आए। यूरिया एवं डीएपी की पर्याप्त उपलब्धता के साथ-साथ उनकी

उचित कीमत पर आपूर्ति भी सुनिश्चित की जा रही है।

कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड में अंकित सिफारिश के अनुसार ही उर्वरकों के उपयोग हेतु प्रेरित करने, उर्वरकों का समान रूप से पारदर्शिता के साथ वितरण कराने और उर्वरक वितरण में अनियमितता बरतने वाले विक्रेताओं, जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हेतु समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

विभाग द्वारा समस्त किसानों को समान रूप से उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के लिए कृषकों को पंक्तिबद्ध किया जाकर उर्वरकों का वितरण प्रशासन के सहयोग एवं विभागियों कार्मिकों की देख-रेख में किया जा रहा है। राज्य में सरसों फसल की अग्रिम बुवाई करने वाले जिलों में किसानों द्वारा डीएपी का क्रय कर अग्रिम भण्डारण किया जा रहा है।

‘भजनलाल सरकार ने 80-90 प्रतिशत बजट घोषणाओं को क्रियान्वित किया’

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर । राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी ने मंगलवार को जयपुर में प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संवाद में सांसद एवं विधायकों को केन्द्र और राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों को अधिक से अधिक आमजन तक पहुंचाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करने का आग्रह किया है।

चतुर्वेदी ने बताया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार ने अपने बजट की 80 से 90 प्रतिशत से अधिक बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन किया है। राम जलसेतु लिंक परियोजना और यमुना जल समझौते को मूर्त रूप प्रदान किया। वहीं, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय में ईआरसीपी की योजनाओं पर गंभीरता से कार्य नहीं हुआ और केवल राजनीति हुई। उस समय जब तत्कालीन जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत जल परियोजनाओं पर बैठक लेने आए तो पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्री बैठक से नदारद रहे। चतुर्वेदी ने कहा कि राज्य सरकार ने हर क्षेत्र और हर वर्ग के विकास के लिए कार्य किया है। लगभग 75 हजार पदों पर सरकारी नियुक्तियां प्रदान की गईं। आने वाले कुछ दिनों में 15-20 हजार सरकारी भर्तियों की घोषणा होने वाली है। हमारी सरकार, पहली सरकार है जिन्होंने सरकारी भर्तियों का कैलेण्डर जारी किया है। उन्होंने कहा कि यूरिया और खाद की आपूर्ति प्रदेशभर में सुनिश्चित की जा रही है तथा इनकी कालाबाजारी को प्रभावी रूप से रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई की जा रही है।

नामांकन के बाद विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित हों : राज्यपाल शैक्षिक उत्कृष्टता के लिए निरंतर कार्य हो, ताकि राजस्थान देश का अग्रणी राज्य बने : हरिभाऊ बागडे

जयपुर । राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कुलगुरुओं को व्यक्तिगत रूचि लेकर शैक्षिक उत्कृष्टता के लिए कार्य करने का आह्वान किया है। उन्होंने विश्वविद्यालयों में नामांकन के बाद विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने, इस हेतु अच्छे ढंग से पढ़ाने, रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रमों से उन्हें जोड़ने आदि के लिए भी कार्य करने पर जोर दिया। उन्होंने राजस्थान को उच्च शिक्षा में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए कार्य करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों में सुधार हो, नहीं तो उनके खिलाफ भी कड़े कदम उठाए जाएंगे।

राज्यपाल बागडे मंगलवार को राजभवन में विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा बैठक में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विश्वविद्यालयों में नैक शिक्षा नीति लागू करने, विश्वविद्यालयों में नैक एंक्रिडिएशन की कार्यवाही पूर्ण करने, वहां उपलब्ध लैब, पुस्तकालय, खेल मैदानों और छात्रावास के बारे में भी विस्तार से जानकारी ली।

उन्होंने कहा कि सभी विश्वविद्यालयों में एक समान प्रश्नपत्र और पाठ्यक्रम लागू किए जाने की व्यावहारिकता के बारे में भी सुझाव लिए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के गोद लिए गानों को पिपलॉली पैटर्न पर विकसित किया जाए। वहां पर अच्छे छायादार पौधे, फल, प्राकृतिक खेती के लिए भी लोगों को प्रोत्साहित कर कार्य किया जाए।

राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों में शोध के अंतर्गत मौलिक दृष्टि रखे जाने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में पेंशन, वेतनमान आदि के लिए भी राज्य सरकार स्तर पर संवाद कर सकारात्मक प्रयास किए जाएंगे।

जल जीवन मिशन के 900 करोड़ के टैंडर घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी को राहत नहीं राजस्थान हाईकोर्ट ने महेश जोशी की जमानत याचिका खारिज की

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े ईडी प्रकरण में आरोपी पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी को राहत देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में महेश जोशी की ओर से दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने यह आदेश महेश जोशी की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए दिए। एकलपीठ ने गत 8 अगस्त को मामले में फैसला सुरक्षित रखा था।

इस मामले में ए.सी.बी. की 2 तथा सीबीआई की एक एफ.आई.आर. समेत कुल 4 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। जिससे ईडी की ओर से चारों मामलों को संयुक्त तरीके से जांच जा रहा है। इस मामले में ईडी की ओर से अधिवक्ता अश्वय भारद्वाज ने हाईकोर्ट में बताया कि, पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार में मंत्री जलदाय मंत्री रहे महेश जोशी ने इस जल जीवन मिशन घोटाले में मुख्य भूमिका निभाई है। अगर महेश जोशी, मंत्री के पद पर नहीं होते तो इस घोटाले को अंजाम नहीं दिया जा सकता था। उन्होंने कहा कि, इस मामले में मुख्य दलाल संजय बडाय़ा, पदमचंद जैन, महेश जोशी व उनके पुत्र रोहित जोशी, मंगललाल सेनी समेत 18 लोगों की भूमिका संदिग्ध है। ईडी की ओर से कहा गया कि, इस मामले में संजय बडाय़ा ने पदमचंद जैन

- ईडी की ओर से अदालत में कहा गया कि, पदमचंद जैन और अन्य लोगों की फर्मों ने फर्जी “ईस्कॉन सर्टिफिकेट” पेश करके यह टैंडर हासिल किए थे
- ईडी का कहना था कि, इस 900 करोड़ के टैंडर में से 620 करोड़ रु. तो पूर्ववर्ती अशोक गहलोत की सरकार के समय ही रिलीज कर दिए थे, जबकि इन फर्मों का काम आंशिक हुआ था
- ईडी का कहना है कि, मामले में घोटाले की पूरी राशि 625 करोड़ रु. मानी जानी चाहिए, हालांकि उनके पास 5.50 करोड़ की घूस राशि के लेन-देन का पुख्ता सबूत है। अभी भी ई.डी. इस मामले में जांच कर रही है।

और पीपूष जैन को 900 करोड़ रु. का टैंडर दिलवाया। परंतु जल जीवन मिशन में टैंडर डालने के लिए सिर्फ वही कंपनियां भाग ले सकती थी, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत “ईस्कॉन इंटरनेशनल लि.” द्वारा मान्यता प्राप्त हो। गौरतलब यह है कि इस मामले में जिन कंपनियों को 900 करोड़ रु. तक के टैंडर दिए गए, उनमें से किसी के पास भी यह सर्टिफिकेट नहीं था। इन फर्मों ने फर्जी दस्तावेज और सर्टिफिकेट लगाकर यह टैंडर हासिल किए थे। ई.डी. की जांच में यह भी सामने आया कि, पीएचईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी पारितोष गुप्ता ने फर्जी सर्टिफिकेट की जांच करने हेतु “ईस्कॉन” को सत्यापन के लिए ई-मेल भेजा था। जिस पर “ईस्कॉन” की ओर

से जवाब दिया गया था कि उन्होंने इन कंपनियों को कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया, जिन्होंने राजस्थान में जल जीवन मिशन के टैंडरों में भाग लिया। जैसे ही तत्कालीन मंत्री महेश जोशी को इस बात का मालूम चला तो अधिकारी पारितोष गुप्ता का अन्यत्र स्थानांतरण कर दिया गया था।

ई.डी. की ओर अदालत में कहा गया कि, उनके पास कई अधिकारी-कर्मचारियों के बयान हैं कि, उन्हें तत्कालीन मंत्री महेश जोशी ने अनौपचारिक आदेश देकर देखे थे कि संजय बडाय़ा के कबे अनुसार काम करो, अन्यथा तबादला कर दिया जायेगा।

ईडी का कहना है कि फर्जी “ईस्कॉन सर्टिफिकेट” के आधार पर पदमचंद जैन और अन्य फर्मों को 900

करोड़ का टैंडर मिला। इसमें से पिछली अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में ही 625 करोड़ रु. की मंजूरी दी जा चुकी थी तथा 620 करोड़ रु. रिलीज कर दिए गए थे। जबकि इन फर्मों द्वारा आंशिक कार्य ही किया गया था।

ई.डी. का कहना है कि, इस 625 करोड़ रु. की राशि को ही घोटाले का मूल आधार माना जाए। ईडी की जांच में 5.5 करोड़ रु. की धांधली का स्पष्ट उजागर हुई है। इसमें से 3.3 करोड़ रु. संजय बडाय़ा ने बतौर कमीशन नकद लिया। शेष 2.1 करोड़ रु. का 50 प्रतिशत हिस्सा महेश जोशी के बेटे की कंपनी में दिया गया। बाकी बचे हुए 1.06 करोड़ रु. महेश जोशी के बेटे ने संपत्ति खरीदी।

ईडी की ओर से अधिवक्ता अश्वय भारद्वाज ने कहा कि महेश जोशी के बेटे की फर्म “शुभ मोलम” में 50 लाख रुपए का लेनदेन किया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से इस राशि को लौटाना भी बताया जा रहा है तो राशि लौटाने से अपराध की गंभीरता कम नहीं होती है। वहीं महेश जोशी की ओर से जमानत याचिका में अदालत को बताया कि प्रकरण में उसे फंसाया गया है। प्रकरण को लेकर एसीबी ने दर्ज मूल केस में याचिकाकर्ता का नाम नहीं है। याचिकाकर्ता को एक साल पहले नोटिस दिया गया। इसके बाद बिना कोई परिस्थिति बदले उसे गत अप्रैल माह में

गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा ईडी याचिकाकर्ता पर 2.01 करोड़ रुपए का आरोप लगा रही है, जबकि इसे लेकर ईडी के पास कोई साक्ष्य नहीं है और परिवारी यह राशि कहा से लाया, उसका भी उल्लेख नहीं है। इसके अलावा ईडी ने अपनी रिपोर्ट में बेटे की फर्म में 50 लाख रुपए का लेनदेन बता रही है। यह राशि बेटे की कंपनी ने लोन के तौर पर ली थी और उसे लौटाया भी जा चुका है। वहीं इस राशि को लेकर सिविल केस भी लंबित चल रहा है। ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाए।

हालांकि जिरह के दौरान यह स्पष्ट हो गया था कि संजय बडाय़ा के कहने पर ही पदमचंद जैन व अन्य कंपनियों ने महेश जोशी के बेटे की फर्म में 50 लाख रु. डाले थे। ईडी ने जब उनसे पूछा कि क्या वह महेश जोशी के बेटे को जानते हैं अथवा पहचानते हैं तो उन्होंने इनकार कर दिया। इस पर ईडी की ओर से कहा गया कि, यह घूस की राशि है, ऐसे अनजान लोगों को ऋण कौन देता है। याचिकाकर्ता और उसके बेटे ने विभाग की टैंडर प्रक्रिया में रिखत प्राप्त की है। यदि आरोपी को जमानत दी गई तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए उसकी जमानत याचिका को खारिज किया जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी महेश जोशी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

जयपुर जिले से 4905 वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा तीर्थ यात्रा का अवसर

जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने निकाली ऑनलाइन लॉटरी

जयपुर । राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना-2025 के तहत जयपुर जिले के 4 हजार 905 वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा का अवसर मिलेगा। मंगलवार को देवस्थान मंत्री जोगाराम कुमावत की मौजूदगी में जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम

- देवस्थान मंत्री जोगाराम कुमावत सहित अन्य जनप्रतिनिधि रहे मौजूद**
- 526 सफल आवेदक हवाई जहाज से तथा 4379 रेल से करेंगे तीर्थ यात्रा**



देवस्थान मंत्री जोगाराम कुमावत की मौजूदगी में जयपुर जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना-2025 की ऑनलाइन लॉटरी निकालकर सफल आवेदकों की घोषणा की।

526 यात्री हवाई मार्ग से काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर की यात्रा करेंगे, जबकि 4 हजार 379 यात्री रेल मार्ग से विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करेंगे। योजना के तहत जयपुर जिले के कुल आवेदन 11 हजार 378 एवं कुल यात्री 18 हजार 423 प्राप्त हुए।

उन्होंने बताया कि रेल यात्रा के लिए चयनित वरिष्ठ नागरिकों को हरिद्वार-त्र्यंघ्रिवेनश-अयोध्या-वाराणसी-सारनाथ, समेदशिवर-पावापुरी-वाराणसी-सारनाथ, मथुरा-वृंदावन-बरसाना-आगरा-अयोध्या, द्वारकापुरी-नागेश्वर-सोमनाथ, तिरुपति-पदमावति, कामाख्या-गुवाहाटी, गंगासागर-कोलकाता, जगन्नाथपुरी-कोणार्क, रामेश्वरम-मदुरई, वैष्णो देवी-अमृतसर-वाघा बोर्डर, गोवा के मंदिर एवं अन्य स्थल चर्च आदि, महाकालेश्वर-उज्जैन-ओं नगरे श्वर-त्रयम्बावेऽश्वर-घृष्णेश्वर-ऐलोरा, बिहार शरीफ, पटनासाहिब पटनाबिहार, श्री हजुर साहिब नंदेड जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों का दर्शन करवाया जाएगा।

इस अवसर पर देवस्थान मंत्री जोगाराम कुमावत ने बताया कि राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना वरिष्ठ नागरिकों को

धार्मिक स्थलों के दर्शन का अवसर देकर उनके जीवन में आध्यात्मिक संतोष और मानसिक शांति का संचार करती है। यह यात्रा ना केवल व्यक्तिगत अनुभव है बल्कि सामूहिकता, मेल-जोल और सामाजिक संबंधों को भी सुदृढ़ करती है।

उन्होंने बताया कि 70 वर्ष से अधिक आयु के यात्री अपने साथ एक अटेंडेंट ले जा सकते हैं। साथ ही, यदि पति-पत्नी में से एक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक और दूसरे की आयु 58 वर्ष है तो दोनों को एक साथ यात्रा की अनुमति है। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि यात्रा के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए। इसके लिए प्रत्येक दल के साथ चिकित्सा स्ट्याफ, सुरक्षा कर्मी और सरकारी कर्मचारी यात्रा करेंगे।

राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, विधायक चंद्रप्रकाश आख्या, जीवाराम चौधरी, अशोक कोठारी, प्रियंका चौधरी जिला कलक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी, अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) देवेन्द्र कुमार जैन और देवस्थान विभाग के अतिरिक्त निदेशक रतनलाल योगी सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

‘दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के आवेदन ऑनलाइन प्रोसेस करें’

जयपुर । प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंगलवार को स्वास्थ्य भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित दिव्यांगता प्रमाण-पत्र को आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन किए जाने के निर्देश जारी किये गये। बैठक में मौसमी बीमारियों सहित विषयों पर भी समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। मिशन निदेशक एनएचएस डॉ. अमित कुमार यादव, अतिरिक्त मिशन निदेशक एनएचएस डॉ.टी. शुभमगला, निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश शर्मा ने मौसमी बीमारियों, टीबी मुक्त अभियान, एनसीडी गतिविधियों, यूडीआईडी कार्ड, मेडिको लीगल केस, अपंजीकृत चिकित्सक एवं प्रयोगशालाओं के विकसर्ग की गयी कार्यवाहियों, आरजीएचएस व आयुष्मान योजना, राज हैथ्य पोर्टल पर चिकित्सा संस्थानों व स्वास्थ्यकार्मिकों की मैपिंग कार्य के दिशा-निर्देश दिये।

मंत्री अविनाश गहलोत ने की समाज कल्याण से जुड़े कार्यों की समीक्षा बजट घोषणाओं की शत प्रतिशत क्रियान्विति करने के निर्देश दिए

जयपुर । सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि बजट घोषणाओं की क्रियान्विति शत-प्रतिशत होना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि घोषणाओं के बेहतर क्रियान्वयन से ही आमजन को लाभ पहुंच सकता है। गहलोत मंगलवार को मुख्यालय के अंबेडकर भवन के सभागार में आयोजित विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

उन्होंने बजट घोषणा वर्ष 24-25 एवं 25-26 की बिंदुवार प्रगति रिपोर्ट ली और लंबित कार्यों के लिए विशेष कार्ययोजना बनाकर काम करने के निर्देश दिए। इस दौरान विधानसभा में विशेष योग्यजन, पेंशन, छात्रवृत्ति, महिला कल्याण, छात्रावास सहित अन्य विषयों से जुड़े प्रश्नों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई।

सामाजिक न्याय मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा समाज के वंचित तबके को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से लाभान्वित करना है। उन्होंने बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के वंचित भौतिक सत्यापन की स्थिति, छात्रवृत्ति की वित्तीय भौतिक प्रगति, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में चयनित अभ्यर्थियों में से कोचिंग संस्थानों में ज्वाइन किए गए



सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने मंगलवार को अधिकारियों की बैठक लेकर विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति जानी।

निर्देश भी दिए। निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आशीष मोदी ने कहा कि वर्ष 2024-25 की कुल 26 बजट घोषणाओं में से 13 पूर्ण हो चुकी है, 10 प्रगतिरत है। जबकि 3 प्रक्रियाधीन है। वहीं वर्ष 25-26 की 15 घोषणाओं में से 8 पूर्ण हो चुकी है, 4 प्रगतिरत है, जबकि 3 प्रक्रियाधीन है। उन्होंने बताया कि सभी घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया जा रहा है।बैठक में आयुक्त निदेशालय विशेष योग्यजन केसर लाल मोना, वित्तीय सलाहकार अंजु सिंह, निजी सचिव रोहित पटेल, अतिरिक्त निदेशक हरिसिंह मोना, रीना शर्मा, सुण्डरायण सीना, अशोक गिंगड़, अरविन्द कुमार मीना, अनुजा निगम के वीरेन्द्र सिंह सहित बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्यजन विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

